

साप्ताहिक मौसम		
दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	23°	10°
शनिवार	25°	11°
रविवार	24°	13°
सोमवार	25°	14°
मंगलवार	24°	14°
बुधवार	25°	13°
बिस्वा	22°	15°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

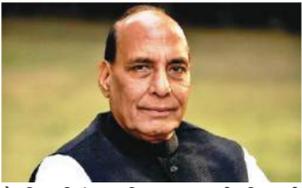
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

डीएसी ने 3.60 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी, 2026 को लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर सेवाओं के विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएएफ) (राफेल), लड़ाकू मिसाइलों और एयर-शेप आधारित उच्च ऊंचाई वाले छत्र उपग्रह (एएस-एचएपीएस) की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी गई।

एमआरएएफ की खरीद से युद्ध की सभी स्थितियों में हवाई वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ वायु सेना की निवारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। खरीदी जाने वाली अधिकांश एएमआरएएफ मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये लड़ाकू मिसाइलें गहरी मार्क क्षमता और अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी। एएस-एचएपीएस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों



के लिए निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना को विभव (एटी-टैंक माइंस) की खरीद और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (एआरवी), टी-72 टैंकों और पैदल सेना लड़ाकू वाहनों (बीएमपी-II) के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण के लिए मंजूरी दी गई है। विभव माइंस को दुश्मन की मशीनीकृत सेनाओं की बढ़त में देरी करने के लिए एटी-टैंक बाधा प्रणाली के रूप में बिछाया जाएगा। एआरवी, टी-72 टैंकों और बीएमपी-2 के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण से उपकरणों का सेवा जीवन बढ़ेगा। इससे भारतीय सेना

की तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। भारतीय नौसेना को 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर और पी8आई लम्बी दूरी के समुद्री टोही विमान के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-वैन श्रेणी के तहत 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर के शामिल होने से विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी। इससे भारतीय नौसेना की बिजली उत्पादन आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। पी8आई विमान के अधिग्रहण से नौसेना की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को डॉनियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। यह खरीद आईसीजी की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी।

दूरदर्शन की दिग्गज एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

नई दिल्ली. दूरदर्शन की दिग्गज समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का दिल्ली में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सार्वजनिक प्रसारक ने गुरुवार को यह घोषणा की जिसके बाद सहकर्मियों और प्रशंसकों की ओर से श्रद्धांजलि का ताता लग गया। डीडी न्यूज़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दूरदर्शन की दिग्गज एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया; वह 1980 के दशक में डीडी न्यूज़ के सबसे परिचित और प्रसिद्ध चेहरों में से एक थीं। उनकी मृत्यु पर दर्शकों, सहकर्मियों और प्रशंसकों की ओर से शोक संवेदनाओं का ताता लग गया जो उनकी शांत उपस्थिति और आकर्षक प्रस्तुति शैली को याद करते हैं। माहेश्वरी को दूरदर्शन की प्रतिष्ठित समाचार एंकरों में से एक माना जाता था।



अमृतसर में सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश 7.6 किलोग्राम हेरोइन व 21 हजार रुपये की ड्रग मनी सहित दो गिरफ्तार

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो गुर्गों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन और 21,800 रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार करके इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साहिबप्रत सिंह उर्फ साहिब (19), निवासी फतेहगढ़ चंडिया, बटाला और वर्तमान पता छेरटा, अमृतसर तथा गगनदीप सिंह उर्फ गगन (26) निवासी गुरु नानकपुर, कोट खालसा, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों मुलजिम अपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा लूटपाट से संबंधित मामले दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम वचुअल नंबरों के माध्यम से दुबई स्थित एक हैंडलर के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान से ड्रग के जरिए हेरोइन की खेप भेजना सुनिश्चित करता था और पिकअप स्थानों तथा सप्लाय चैन के बारे में निर्देश देता



था। उन्होंने बताया कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है और 43 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित एक बड़े एनडीपीएस केस से भी जुड़ा हुआ है। डीजीपी ने बताया कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और दोनों संदिग्धों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन तथा ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया। सीपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है।

यूएन रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा लाल किला अटैक में जैश का हाथ

नई दिल्ली. दक्षिण एशिया में आतंकवाद से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की 37वीं रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) को 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले से जोड़ा है, जिसमें कथित तौर पर 15 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, एक सदस्य देश ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

इससे पहले, 8 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर ने संगठन के लिए एक अलग महिला शाखा, जमात-उल-मुमिनात के गठन की घोषणा की थी। हालांकि यह नई शाखा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इस पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। रिपोर्ट में जैश-ए-तैबा की मौजूदा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच मतभेदों पर भी प्रकाश डाला

गया है; एक देश का कहना है कि संगठन अभी भी सक्रिय है, जबकि दूसरा देश दावा करता है कि यह "निष्क्रिय" हो गया है। वहीं, पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद जैश-ए-तैबा और लश्कर-ए-तैबा दोनों ही अब सक्रिय नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगांम हमले का भी जिक्र है, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला प्रतिरोध मोर्चा द्वारा किया गया था, जिसे लश्कर-ए-तैबा का सहयोगी संगठन माना जाता है। 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही हुई आई20 में हुए भीषण विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई। विस्फोट में कई अन्य लोग घायल हो गए और आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, जिससे इलाके में व्यापक क्षति हुई। प्रारंभिक जांच में इस घटना का संबंध फरीदाबाद में हाल ही में उजागर हुए एक संदिग्ध आतंकी मांड्यूल से जोड़ा गया है।

4000 रुपए रिश्त लेता नायब कोर्ट रंगे हाथों काबू

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान पंजाब होम गार्ड (पीएचजी) के पी. सी. नायब कोर्ट शरनदीप सिंह, जो कि थाना श्री मुक्तसर साहब के साथ सम्बन्धित है, को 4000 रुपए रिश्त लेते रंगे हाथों काबू किया है। राज विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी वक्ता ने कहा कि उक्त दोषी को श्री मुक्तसर साहब के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि दोषी शरनदीप सिंह ने अदालती केस में उसकी मदद करने के बदले 4000 रुपए रिश्त की मांग की थी। इस सम्बन्धित दोषी ने अलग-अलग मौकों पर उसकी जमानत रद्द हो गई है या नहीं, बारे जानकारी देने के लिए रिश्त की मांग की थी।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक जाल बिछाया जिस दौरान दोषी को सरकारी गवाहों की हाज़री में शिकायतकर्ता से 4000 रुपए की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्बन्धित दोषी विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो के थाना बटिंडा में भ्रष्टाचार रोकू कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे वाली जांच जारी है।

पीएम मोदी 13 फरवरी को 'सेवा तीर्थ' करेंगे राष्ट्र को समर्पित

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 तथा कर्तव्य भवन-2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक शासन संरचना में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्था क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुरानी अवसंरचनाओं से कार्य करते रहे। प्रमुख कार्यालयों के इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएं, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं से युक्त नए भवन परिसर के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समर्पित करके इन समस्याओं से अब मुक्ति मिल जाएगी। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सूचारु संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी।

जीएसटी घोटाले और आंतरिक अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : हरपाल सिंह चीमा

लंबे समय से गैर-हाज़िर रहने के कारण आबकारी एवं कर इस्पेक्टर सेवा से बर्खास्त

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की वित्तीय ईमानदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि लुधियाना के एक कारोबारी को 9 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आबकारी एवं कर इस्पेक्टर को लंबे समय से बिना सूचना के गैर-हाज़िर रहने के कारण नौकरा से बर्खास्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्टेट इंटीलजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (सीआईपीयू), लुधियाना के विभाग ने मेसर्स एम.ए.ए. स्टील, लुधियाना के मालिक रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, "कराधान विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जहां मेसर्स एम.ए.ए. स्टील द्वारा बिना किसी वास्तविक सप्लाय के एच.आर./सी.आर. कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रिप्स के जाली इनवॉइस जारी किए जा रहे थे। इस थोखाधड़ी वाले नेटवर्क के द्वारा 9 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) विभिन्न लाभार्थियों को दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को सीधा और बड़ा नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान विभाग की टीमों ने मौके पर मौजूद स्टॉक और फर्म के आधिकारिक बुक रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर पाया है।"

वित्त मंत्री ने बताया कि इस मामले में जांच का दौरा और बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने एक आबकारी एवं कर इस्पेक्टर को लंबे समय से गैर-हाज़िर रहने के कारण पंजाब सिविल सर्विसेज़ (सज़ा और अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासन के प्रति पंजाब सरकार के सख्त रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "भ्रष्टवत् मान सरकार इस बात के लिए धुंध है कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पहले भी ऐसी अनुशासनहीनता के कारण चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुके हैं और एक अन्य आबकारी एवं कर इस्पेक्टर तथा एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है।"

वित्त मंत्री ने बताया कि इस मामले में जांच का दौरा और बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने एक आबकारी एवं कर इस्पेक्टर को लंबे समय से गैर-हाज़िर रहने के कारण पंजाब सिविल सर्विसेज़ (सज़ा और अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासन के प्रति पंजाब सरकार के सख्त रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "भ्रष्टवत् मान सरकार इस बात के लिए धुंध है कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पहले भी ऐसी अनुशासनहीनता के कारण चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुके हैं और एक अन्य आबकारी एवं कर इस्पेक्टर तथा एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है।"

एक माह में दूसरी बार जालंधर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान 'ऑपरेशन लोटस' के तहत भाजपा ने दिया बड़ा ऑफर : 'आप' विधायक

• जालंधर ब्रीज. जालंधर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को जालंधर में अपने निवास स्थान पर 'लोक मिलनी' कार्यक्रम आयोजित कर यहां के नागरिकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर उनके मुद्दों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करता है। 'आप' सरकार पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है, जो जवाबदेह



और पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करता है, और इसे आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों का निपटारा करने और सूचारु रूप से शासन संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित



पहल देखने को मिले। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो आम जनता की भलाई के लिए ऐसी लोक-केंद्रित पहल कर रहा हो। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड पर शिकायतों का निपटारा करने और सूचारु रूप से शासन संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित

की समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करती है। इस पहल को पंजाब के लिए गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसी मुहिम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता है।

कहा- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संगरूर से भाजपा की टिकट देने का दिया लालच

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज ने एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राजनीतिक धमारे करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भराज ने खुलासा किया कि भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनसे संपर्क साधा और बंद कर्म में मीटिंग करने सहित भाजपा की टिकट दिलाने और मनमानी शर्तें पूरी करने का बड़ा ऑफर दिया। गुरुवार को पार्टी ऑफिस में स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पट्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरिंदर कौर भराज ने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' चला रही है। हाल ही में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे संगरूर से भाजपा की टिकट देने का लालच दिया और कहा कि मेरी जो भी मांग है, वह पूरी की जाएगी। भराज ने आगे



कहा कि वह 2014 में सिर्फ 19 साल की उम्र में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं वो कार्यकर्ता हूँ जिसने पार्टी के लिए पोस्टर लगाए हैं। एक छोटे किसान की बेंटी को 27 साल की उम्र में विधायक बनाने का सम्मान सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए भराज ने कहा कि सैनी साहब आजकल जिस तरह पंजाब की गलियों में घूम रहे हैं, उससे लगता है कि भाजपा ने उन्हें डेप्युटेशन पर पंजाब भेजा है। मेरी उन्हें सलाह है कि मेरी चिंता कंजना छोड़ दें और अपने हरियाणा की चिंता करें। पंजाब की जनता और आप विधायक चट्टान की तरह मान साहब और केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं।

सावधान! डिमेंशिया के 50 प्रतिशत मामलों के पीछे छिपी हैं आपकी ये रोजमर्रा की गलतियां

Expert View

डॉ. कहते हैं कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में धीरे-धीरे होने वाली कमी का समूह है, जिसमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों का नाम भी...

• जालंधर ब्रीज . फीचर

डिमेंशिया को लोग अक्सर बढ़ती उम्र की समस्या मानते हैं, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च कई मामलों का इसका संबंध रोजमर्रा की आदतों से जोड़कर भी देखती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, लगभग आधे डिमेंशिया के मामलों में कई ऐसे जोखिम कारक शामिल होते हैं, जिन्हें सही आदतों को अपनाकर समय रहते कम किया जा सकता है। डॉ. कहते हैं कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में धीरे-धीरे होने वाली कमी का समूह है, जिसमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों का नाम भी शामिल है। कई लोगों को यह लगता है कि इस समस्या को रोका नहीं जा सकता, लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़े कई कारण ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल करके जोखिम

कम जरूर किया जा सकता है। डिमेंशिया का खतरा बढ़ाते हैं ये कारण द लैसेट में प्रकाशित एक रिसर्च में जिन प्रमुख लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात सामने आई है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ जैसे डिप्रेशन शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक अलगाव, कम शिक्षा, सुनने की समस्या, अत्यधिक शराब का सेवन और प्रदूषण जैसे कारक भी जोखिम बढ़ा सकते हैं।

डिमेंशिया के खतरे को दूर रखती हैं ये आदतें : हमारा दिमाग शरीर के बाकी अंगों की तरह ही स्वस्थ आदतों पर निर्भर करता है। नियमित एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, जिससे ब्रेन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। संतुलित आहार, खासकर हरी सब्जियाँ, फल, नट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड,



मस्तिष्क के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसके साथ ही नींद पूरी लेना, तनाव कम लेना और मानसिक रूप से सक्रिय रहना जैसे पढ़ना, पहलियाँ हल करना या नई

चीजें सीखना दिमाग को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

छोटे ब्रेक लेना भी है जरूरी : आजकल डिजिटल लाइफस्टाइल और बैठकर काम

करने की आदतों ने भी जोखिम बढ़ाया है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहना या लगातार स्क्रीन पर रहना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

इसलिए दिनभर में छोटे-छोटे ब्रेक लेना और सक्रिय रहना जरूरी है।

दिमागी सेहत को अच्छा बनाए रखती हैं ये आदतें : डिमेंशिया की रोकथाम जीवन की किसी एक स्टेज तक सीमित नहीं है। युवा अवस्था से ही हेल्दी आदतें अपनाने से उम्र बढ़ने पर भी दिमाग के स्वस्थ बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराना, धूम्रपान से दूरी और सामाजिक रूप से जुड़े रहना दिमागी स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी कदम हैं।

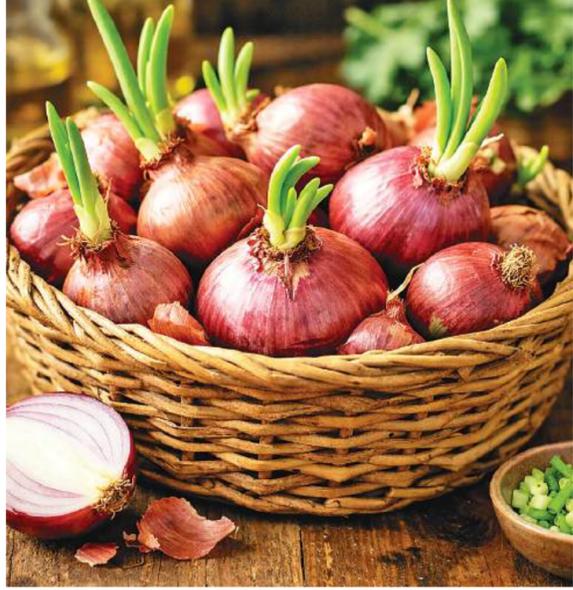
सलाह- अगर परिवार में किसी व्यक्ति में याददाश्त कमजोर होना, बार-बार चीजें भूलना, व्यवहार में बदलाव या रोजमर्रा के कामों में परेशानी जैसे लक्षण दिखें, तो इसे नजरअंदाज न करें और समय पर न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें। सही समय पर पहचान और लाइफस्टाइल में सुधार से डिमेंशिया की गति को कम करके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।

डिस्कलेमर : इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

KITCHEN HAKS

अंकुरित प्याज सेहत के लिए वरदान या जहर? फेंकने से पहले जरूर जान लें ये बातें

क्या अंकुरित आलू की तरह प्याज में भी अंकुर निकलने से उनमें जहरीले तत्व (Solanine) बढ़ने का खतरा बना रहता है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो सीके बिड़ला अस्पताल की डाइटिशियन ने आपकी उलझन दूर



• जालंधर ब्रीज . फीचर

प्याज की टोकरी में लंबे समय से रखे प्याज से जब नन्हे हरे अंकुर निकलने लगते हैं तो लोग अक्सर इस कशमकश में पड़ जाते हैं कि क्या इनका सेवन करें या इन्हें फेंक दें। क्या अंकुरित आलू की तरह प्याज में भी अंकुर निकलने से उनमें जहरीले तत्व (Solanine) बढ़ने का खतरा बना रहता है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो डाइटिशियन ने आपकी उलझन दूर कर दी है। डॉक्टर की मानें तो अंकुरित प्याज न केवल खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि कई मायनों में यह सामान्य प्याज से अधिक पोषिक भी हो सकता है। लेकिन इसका सेवन करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है।

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

डाइटिशियन कहती हैं कि प्याज में से जब अंकुर निकलता है, तो इसका मतलब है कि वह अपने पोषक तत्वों से एक नया पौधा उगा रहा होता है। इस प्रक्रिया में प्याज आलू की तरह जहरीला नहीं हो जाता। आलू में अंकुर आने पर उसमें हानिकारक तत्व बन सकते हैं जबकि प्याज में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा प्याज खाने के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित होता है।

स्वाद पर पड़ता है असर

प्याज में अंकुर आने से उसकी क्वालिटी और स्वाद पर असर जरूर पड़ता है। पोषक तत्व कोषल की तरफ चले जाने से प्याज थोड़ा नरम, सिकुड़ा हुआ और खाने में कम स्वादिष्ट लग सकता है। कुछ लोगों को प्याज के स्वाद में हल्की कड़वाहट भी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर प्याज अभी भी टाइट है और उसमें फर्फूदी या सड़न नहीं है, तो हरी कोषल निकालकर इसे

खाया जा सकता है।

अंकुरित प्याज का कैसे करें इस्तेमाल

प्याज की हरी कोषल खुद भी खाने लायक होती है। इसका स्वाद हल्का प्याज जैसा ही होता है। आप इसे स्त्रिण अनियन की तरह सलाद, सूप, सब्जी, स्टर-फ्राई या गार्निश में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोषण के लिहाज से, अंकुरित प्याज में कुछ एंटीऑक्सिडेंट अधिक मात्रा में भी हो सकते हैं।

कैसे प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए

डॉक्टर कहती हैं कि भले ही अंकुरित प्याज खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है लेकिन कुछ हालातों में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। -अगर प्याज बहुत नरम हो -प्याज छूने पर चिपचिपा लगे -प्याज से बदबू आए -प्याज पर फर्फूदी दिखे -जिन लोगों का पाचन संवेदनशील है, उन्हें अंकुरित प्याज खाने से गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

ये सभी लक्षण प्याज क खराब होने के संकेत हैं।

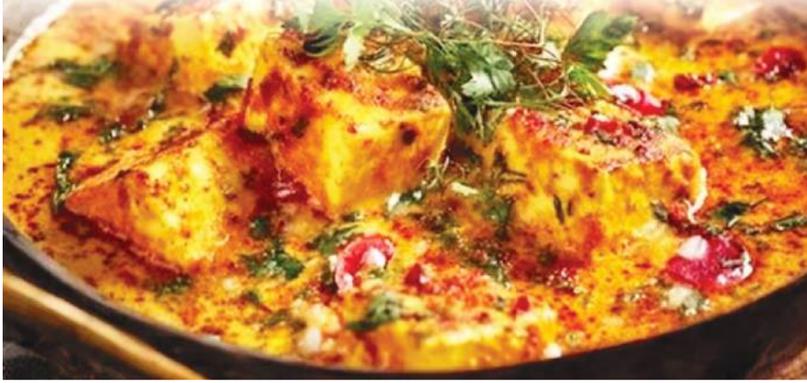
डॉक्टर की सलाह प्याज में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट, सल्फर कंपाउंड और फाइबर दिल की सेहत, इम्यूनिटी और पाचन को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन सेहत के लिहाज से, प्याज चाहे अंकुरित हो या नहीं लेकिन सीमित मात्रा में ही खाना फायदेमंद होता है।

प्याज में अंकुर आने से कैसे रोके प्याज में अंकुर आने से रोकने के लिए प्याज को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। इसके अलावा प्याज को नमी और सीधी धूप से दूर रखें। प्लास्टिक बैग में रखने से बचें, क्योंकि उसमें नमी फंसकर प्याज में अंकुर और सड़न को बढ़ती है।

डिस्कलेमर : इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी स्थिति में एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

बिना टमाटर-प्याज के बनाएं कश्मीरी पनीर यखनी, नोट करें असली पारंपरिक रेसिपी

इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टमाटर या प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। यह ट्रेडिशनल कश्मीरी रेसिपी दही और सौंफ पाउडर से बनी एक सफेद ग्रेवी वाली डिश है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं...



• जालंधर ब्रीज. रेसिपी

अगर आप सर्दियों के मौसम में मुंह का जायका और शरीर को गर्माहट बनाए रखने के लिए कोई कश्मीरी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो अपनी रसोई में ट्राई कर सकते हैं कश्मीरी पनीर यखनी रेसिपी। पनीर यखनी कश्मीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट डिश है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टमाटर या प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। यह ट्रेडिशनल कश्मीरी रेसिपी दही और सौंफ पाउडर से बनी एक सफेद ग्रेवी वाली डिश है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी कश्मीरी पनीर यखनी रेसिपी।

कश्मीरी पनीर यखनी बनाने के लिए सामग्री

- 250 पनीर (मोटे टुकड़ों में कटा हुआ)
- 2 कप दही (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर

आजकल वजन घटाने और बैली फैट कम करने के लिए लोग ग्रीन टी, डिटॉक्स वॉटर और तरह-तरह के घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं। मैंने भी कई ट्रिक्स आजमाई, लेकिन इस बार मैंने एक थोड़ा अलग प्रयोग किया। मेरी न्यूट्रिशनलिस्ट सहेली ने सुझाव दिया कि मैं सुबह नींबू के रस के साथ ब्लैक कॉफी पिऊं, लेकिन सही तरीके से।

मैंने कभी भी इसे खाली पेट नहीं लिया। रोज सुबह उठकर पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिया, फिर 10-15 मिनट बाद नींबू मिलाकर ब्लैक कॉफी ली। इसके साथ मैंने रोजाना मॉर्निंग वॉक भी शुरू की। मैंने यह रूटीन लगातार 30 दिनों तक फॉलो किया। इस दौरान मैंने अपने शरीर में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस किए, खासतौर पर बैली फैट और एनर्जी लेवल को लेकर। यहाँ मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रही हूँ।

एक महीने में मुझे ये बदलाव देखने को मिले : बैली फैट में हल्का लेकिन साफ फर्क: मैंने ये हैक ट्राई किया और लगभग 3-4 हफ्तों में बैली फैट में कुछ अंतर महसूस हुआ। इसके साथ ही पेट फूलने की समस्या भी कम हुई। डाइजेशन में सुधार : नींबू वाली ब्लैक कॉफी से मुझे भारीपन की समस्या कम लगी और सुबह पेट ज्यादा हल्का महसूस हुआ।

एनर्जी लेवल बढ़ा : मॉर्निंग वॉक के बाद मैं यह ड्रिंक लेने से दिनभर सुस्ती कम रही और फोकस बेहतर हुआ। क्रेविंग्स पर कंट्रोल : मुझे मीठा और बार-बार स्नैक करने की इच्छा पहले से कम महसूस हुई, जिससे कैलोरी कंट्रोल में मदद मिली। मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिला : ब्लैक कॉफी और नींबू का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म को हल्का बूस्ट देता है, ऐसा मैंने अपने अनुभव में महसूस किया। सही तरीका बहुत जरूरी है : मैंने कभी भी खाली पेट कॉफी नहीं पी। गुनगुना पानी पहले लेने से एसिडिटी या जलन जैसी समस्या नहीं हुई।

मॉर्निंग वॉक का बड़ा रोल : सिर्फ ड्रिंक नहीं, रोज 30-40 मिनट की वॉक ने फैट लॉस के असर को और भी बेहतर बनाया। इससे ये नुकसान भी हो सकते हैं : खाली पेट लेने पर

- तेल/घी तलने के लिए
- डेढ़ चम्मच सौंफ पाउडर
- 1 चम्मच सोंठ पाउडर
- 2 बड़ी इलायची
- 3-4 छोटी इलायची
- 1 टुकड़ा दालचीनी
- 2-3 लोंग
- 1/2 चम्मच शाही जीरा
- नमक स्वादानुसार
- एक चुटकी सूखी पुदीना की पत्तियाँ (गार्निश करने के लिए)

कश्मीरी पनीर यखनी बनाने का तरीका

कश्मीरी पनीर यखनी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लें। इसके लिए सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें। तलने के बाद पनीर को नमक वाले गुनगुने पानी में डाल दें, इससे पनीर नरम बना रहता है।

दही पकाएँ- अब एक बर्तन में फेंटा हुआ दही डालकर लगातार चलाते रहें ताकि दही में कोई गाँठ

न रहे। अब दही को पैन में डालकर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएँ जब तक इसमें एक उबाल न आ जाए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने दही को चलाना छोड़ दिया, तो दही फट सकता है।

मसाले मिलाएँ- जब दही उबलने लगे, तो इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लोंग और शाही जीरा, सौंफ पाउडर और सोंठ पाउडर डाल दें।

इसके बाद मसालों में पहले से फ्राई किया हुआ पनीर और स्वादानुसार नमक डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक ग्रेवी के गाढ़ा होने तक पकने दें। जब मसालों को खुशबू पनीर में समा जाए तो गैस बंद कर दें।

तड़का और गार्निशिंग- अंत में, ऊपर से थोड़ी सूखी पुदीना की पत्तियाँ क्रश करके डालें। आप चाहे तो ऊपर से एक चम्मच देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। आपका टेस्टी पनीर यखनी बनकर तैयार है, आप इसे बासमती चावल, नान या परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं।

दूर नहीं भागेंगे, किताबों से हो जाएगा प्यार, पेरेंट्स अपनाएं ये असरदार टिप्स

जालंधर ब्रीज (फीचर) : स्मार्टफोन और स्क्रीन की इस चकाचौंध वाली दुनिया में, आज ज्यादातर पेरेंट्स की अपने बच्चों से यही शिकायत है कि उनका मन किताबों से ज्यादा रील देखने में लगता है। आइए जानते हैं वो असरदार तरीके जो कम उम्र से ही आपके बच्चे में किताबों के लिए प्यार को जगा देंगे।

खुद मिसाल बनें : इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे अक्सर कभी भी वो नहीं करते जो उनसे करने के लिए कहा जाता है। वो हमेशा वही चीज दोहराते हैं, जो हमें 'करते' हुए देखते हैं। अगर आप अपना खाली समय फोन स्कॉल करने में बिताते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। दिन में कम से कम आधा घंटा खुद भी कोई किताब या अखबार पढ़ें। जब वह आपको पढ़ते हुए देखेगा, तो उसमें भी किताब पढ़ने की स्वाभाविक इच्छा पैदा होगी।

उनकी पसंद को भी दें सम्मान : ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के लिए कहानी-काटून जैसी किताबें खरीदने के लिए भी अपनी पसंद को शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ ज्ञान वाली या स्कूल से जुड़ी चीजें ही पढ़े। लेकिन शुरुआत में उसे उसकी पसंद चुनने दें- चाहे वह कॉमिक्स हों, डायनासोर की कहानियाँ हों या पतियों के किस्से। एक बार उसे पढ़ने में मजा आने लगा, तो वह धीरे-धीरे गंभीर विषयों को भी उत्साह के साथ पढ़ेगा।

पिक्चर बुक्स' से करें शुरुआत : छोटे बच्चों के लिए शब्द बोझिल हो सकते हैं, लेकिन चित्र उन्हें आकर्षित करते हैं। शुरुआत ऐसी किताबों से करें जिनमें बड़े और रंगीन चित्र बने हुए हों। चित्रों को देखकर बच्चा खुद अपनी कहानी बुनने लगता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और किताबों के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है।

नियम नहीं, रस्म बनाएं : पढ़ने को कभी भी होमवर्क की तरह पेश न करें। रात को सोने से पहले 15 मिनट 'बेडटाइम स्टोरीज' की एक रस्म बना लें। जब आप किरदारों की आवाजें बदलकर या चहरे के हाव-भाव के साथ कहानी सुनाते हैं, तो बच्चा उस कहानी को जीने लगता है। यह समय बच्चे के साथ आपके बॉन्ड को भी मजबूत करता है।

लाइब्रेरी और बुक फेयरों से करवाएं सैर : महीने में एक बार बच्चे को किसी अच्छी लाइब्रेरी या बुकस्टोर लेकर जाएं। वहाँ उसे किताबों की अलमारियों के बीच घूमकर अपनी पसंद की कोई भी एक किताब खुद निकालने के लिए कहें। जब बच्चा अपनी पसंद की किताब खुद चुनता है, तो उसे पढ़ने की जिम्मेदारी और उत्साह उसके लिए दोनों बढ़ जाते हैं।

डिस्कलेमर : इस लेख में दी गई सुचना पूरी तरह सोशल मीडिया रोल पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

30 दिन का एक्सपेरिमेंट : नींबू वाली ब्लैक कॉफी और बैली फैट पर असर

Health

वजन घटाने के लिए मैंने एक महीने तक सुबह नींबू वाली ब्लैक कॉफी ट्राई की। सही तरीके और मॉर्निंग वॉक के साथ इस हैक ने मेरे शरीर और बैली फैट पर कुछ दिलचस्प बदलाव दिखाए...



पेट में दर्द: मैंने खुद इसे खाली पेट नहीं पिया क्योंकि ऐसा करने से गैस, पेट दर्द, मिचली जैसी परेशानी महसूस की। आपका पेट संवेदनशील हो तो इसके लिए आप ब्लैक कॉफी से पहले नट्स या सीड्स भी खा सकते हैं। एसिडिटी और सीने में जलन : मैंने महसूस किया कि अगर कॉफी की मात्रा ज्यादा हो जाए या नींबू ज्यादा निचोड़ दिया जाए, तो एसिडिटी, खट्टी डकार या सीने में जलन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। सही मात्रा का ध्यान रखें।

डिहाइड्रेशन का रिस्क : अगर पानी कम पिया जाए और सिर्फ कॉफी पर निर्भर रहा जाए, तो शरीर में पानी की कमी महसूस हो सकती है। हाइड्रेशन को खास ख्याल रखें।

डिस्कलेमर : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

AI कैसे बदल सकता है भारत के किसानों की तकदीर?

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा सिर्फ नई तकनीक के रूप में नहीं हो रही है। ध्यान इस बात पर जा रहा है कि एआई आम लोगों की असली समस्याएँ कैसे हल कर सकता है। खेती और खाद्य क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ समस्याएँ छोटी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से जुड़ी हैं। यहाँ कोई भी तकनीक तभी सफल होगी जब वह मौसम, ढुलाई और बाज़ार जैसी स्थानीय परिस्थितियों को समझे।

भारत इतना भोजन पैदा करता है कि पूरी आबादी का पेट भर सके, फिर भी हर साल करीब 6.8 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। कटाई के बाद 35 से 40 प्रतिशत फल और सब्जियाँ खराब हो जाती हैं। यह समस्या उत्पादन की कमी की नहीं, बल्कि सही समय पर सही

जानकारी और बेहतर व्यवस्था न होने की है। यानी खेत से बाज़ार तक तालमेल की कमी है और फसले समय पर नहीं हो पाते। ऐसे में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया एआई इस नुकसान को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

क्यूज़ैस लैब्स में हमने इस बात पर गौर किया कि भारत की डिजिटल व्यवस्था ने भुगतान, पहचान और सेवाओं को बदल दिया है, लेकिन खाने के क्षेत्र में गुणवत्ता की जाँच अब भी पुराने तरीकों से होती है। इसी सोच के साथ हमने QScan नाम की एआई तकनीक विकसित की, जो इन्फ्रारेड तकनीक और कृत्रिम सूंघने की मदद से फल-सब्जियों की अंदर की गुणवत्ता पहचानकर तुरंत काम आने वाली जानकारी देती है। उदाहरण के तौर पर कोई फल या सब्जी कितने दिन तक चल सकती है कितने दिन स्टोर कर सकते हैं



रवल चिब
(सह-संस्थापक, क्यूज़ैस लैब्स)

इत्यादि। इसका मकसद कम मुनाफे पर काम करने वाले किसानों, दुकानदारों और ग्राहकों की उलझन कम करना है। अनुभव बताते हैं कि एआई तभी सफल होगा जब वह भारत की वास्तविक

परिस्थितियों को समझे। विदेशों के डेटा पर बने मॉडल भारत जैसे विविध देश में अक्सर सही काम नहीं करते, क्योंकि हर क्षेत्र में फसल, मौसम, भंडारण और बाज़ार अलग हैं। अगर एआई भारतीय हालात को नहीं समझेगा, तो वह बेकार साबित हो सकता है या गलत नतीजे भी दे सकता है। इसी कारण स्वदेशी एआई पर जोर देना समय की ज़रूरत है। सरकार की India AI Mission पहल दिखाती है कि अब एआई को सिर्फ उन्नत तकनीक नहीं, बल्कि देश के विकास का ज़रूरी साधन माना जा रहा है। भारतीय डेटा, देश में बने समाधान और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए खास तकनीक को बढ़ावा देकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ नवाचार सीधे लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा हो। खाद्य और खेती का क्षेत्र बताया है कि यह क्यों ज़रूरी है। अगर कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम हो जाए,

तो किसानों की आय बढ़ेगी, खाने की कीमतें स्थिर रहेंगी और पानी, जमीन और ऊर्जा को बचत होगी। इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और पूरी व्यवस्था ज्यादा मजबूत बनेगी। एक और ज़रूरी पहल है सबकी भागीदारी। एआई ऐसा होना चाहिए जो छोटे किसानों, स्थानीय भाषाओं और छोटे बाज़ारों में भी आसानी से काम कर सके। जो तकनीक लोगों पर फसले थोपेगी, उस पर धरोसा नहीं बनेगा। लेकिन जो तकनीक छिपी जानकारी को आसान तरीके से सामने लाकर बेहतर फसले लेने में मदद करेगी, वही लंबे समय तक टिकेगी और फैल सकेगी।

16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला India AI Impact Summit ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया एआई के असर पर गंभीर चर्चा कर रही है। भारत के पास मौका है कि वह ऐसा रास्ता दिखाए जहाँ एआई आम

लोगों के काम आए, स्थानीय ज़रूरतों को समझे और असली आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो। खेती, खाद्य आपूर्ति और जलवायु से जुड़ी चुनौतियाँ इस दिशा के केंद्र में हैं। यह भी समझना ज़रूरी है कि एआई अपने-आप बदलाव नहीं लाता। इसके लिए सही समझ, सही नीति और मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसे सही तरीके से अपनाया जाता है, तो यह बिना शोर किए बड़े बदलाव ला सकता है।

इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर असली चुनौती एआई को तेजी से अपनाने की नहीं, बल्कि सोच-समझकर सही जगह इस्तेमाल करने की है। आखिर में सफलता का असली पैमाना यही होना चाहिए कि क्या एआई से भोजन की बर्बादी कम होती है, क्या किसानों की आय बढ़ती है और क्या देश की व्यवस्था मजबूत होती है।

हड़ताल श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

चार नयी श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, भारत की विशाल श्रम शक्ति, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन में आसानी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य, बिना जटिल उद्योग वर्गीकरण की बाधाओं के, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देना है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनिवार्य पहचान पत्र की शुरुआत करते हुए, ये संहिताएँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीधी पहुंच की सुविधा के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, श्रमिकों की भलाई में मदद करेंगी, जिससे वे स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा, समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था, पीड़ित श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव और अनिश्चितता को कम करने में सहायता करेगी। समग्र रूप से, ये उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित एक प्रगतिशील रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक प्रारंभिक कदमों के बावजूद, राजनीतिक रूप से प्रेरित केंद्रीय श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) का एक हिस्सा अक्सर हड़ताल के प्रतिकूल प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना, हड़ताल पर उतर

आता है। ऐसी हड़तालों से विशेष रूप से असंगठित अर्थव्यवस्था के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के पारिश्रमिक को भारी नुकसान होता है, जो अपनी जीविका के लिए दैनिक आय पर निर्भर होते हैं। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, बार-बार होने वाली हड़तालों रचनात्मक और कठोर सामूहिक सोदेबाजी की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत और संतुलित परिणाम हासिल करने की संभावना कम हो जाती है।

समय के साथ, बार-बार हड़ताल बुलाने का प्रयास न केवल अप्रभावी साबित हुआ है बल्कि इसके परिणाम प्रतिकूल भी रहे हैं। बार-बार होने वाली हड़तालों से श्रमिकों में व्यापक थकावट दिखाई पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे आह्वान को या तो नजरअंदाज करते हैं या उनमें शामिल नहीं होते हैं। कुछ मामलों में, श्रमिकों के एक छोटे हिस्से को उनकी इच्छा के विपरीत हड़तालों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इन आंदोलनों की नैतिक वैधता व सामूहिक ताकत और कमजोर हो जाती है। अंततः, यह प्रवृत्ति श्रमिक कल्याण उपायों के समग्र प्रभाव को कम करती है और श्रमिकों के बीच एकजुटता को कमजोर करती है।

हड़तालों के व्यापक परिणाम केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहते। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, दैनिक यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है, और सड़क किनारे के विक्रेताओं,

घरेलू श्रमिकों और छोटे सेवा प्रदाताओं की आजीविका बाधित हो जाती है। इन श्रमिकों के लिए, केवल एक दिन की आय का नुकसान भी आजीविका संकट पैदा कर सकता है, उन्हें अपनी सीमित बचत को खत्म करने तथा गंभीर आर्थिक असुरक्षा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है।

भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) को संवाद, आपसी-बातचीत और नियोक्ताओं तथा सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थायी सौदेबाजी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित एक मॉडल उत्पादन, रोजगार, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बाधित किए बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रभावी और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

भारतीय श्रमिकों को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारु रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घवाधिम में सुरक्षित किया जा सकता है।

विकसित भारत 2047 की ओर स्मार्ट रास्ता – हड़ताल नहीं, बल्कि श्रम संहिता

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

पीढ़ियों से, भारत के श्रमिकों ने एक पुरानी और टुकड़ों में बंटी श्रम प्रणाली का बोझ उठाया है, जो अक्सर उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। असंगठित, संविदा और उभरते गिंग क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक नीति-परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं रही थी, ताकि अनुपालन और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहें। चार श्रम संहिताएँ इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग तीन दर्जन अलग-अलग कानूनों को एक सुसंगत, एकल ढांचे में लाकर, ये संहिताएँ न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है।

एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू), कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी को श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समय में श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम

हित में है।

श्रम संहिताएँ कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं। ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम हैं। 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अस्पष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके।

श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है, जो वे श्रमिकों को प्रदान करने का प्रयास करती हैं। वेतन संहिता सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार, असंगठित, संविदा, गिंग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है। इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज

का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेज विवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है। कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शायद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं। संवाद, नियम-आधारित सुधार और मुद्दा-विशेष पर चर्चा के जरिये श्रमिकों के हित बेहतर तरीके से पूरे किये जा सकते हैं, बजाय इसके कि आपस में टकराव हो, जिससे पारिश्रमिक

हानि, उत्पादन में रुकावट और रोजगार असुरक्षा का जोखिम पैदा होता है-विशेष रूप से श्रम बल के सबसे कमजोर वर्गों के लिए।

यह दावा करना भी गलत है कि श्रम संहिताएँ बिना परामर्श के लागू की गई हैं। सुधार प्रक्रिया में त्रिपक्षीय चर्चाओं के कई दौर, संसद की स्थायी समितियों में विचार-विमर्श और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद शामिल थे। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बातचीत और संस्थागत संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि उन व्यवधानों के द्वारा जो अंततः स्वयं श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचाते हैं।

ट्रेन की खिड़की से नहीं, छत से देखें कश्मीर : बड़गाम - कटरा में विस्टाडोम कोच का तोहफा

जालंधर ब्रीज (जम्मू) : उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में यात्रियों की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है, हाल ही में दिनांक 11 फरवरी से विशेष ट्रेन संख्या 04688/ 04687 जो बड़गाम से बनिहाल तक संचालित की जाती थी, लेकिन स्थानीय लोगों और कश्मीर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करवाने हेतु, विशेष ट्रेन को यात्रा सेवा को बनिहाल की जगह श्री माता वैष्णोदेवी कटरा तक विस्तारित किया गया है, साथ ही कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने वाले पर्यटकों के जम्मू मंडल ने एक बड़ी सौगात प्रदान करते हुए, विशेष ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच लगाया गया है, जिससे यात्री कांच की छत और बड़ी खिड़कियों वाले विशेष कोच में आरामदायक यात्रा का आनंद उठा सकेंगे।

विस्टाडोम कोचों की विशेषताओं की बात करें, तो इन कोचों में चौड़ी कांच की खिड़कियाँ और छत है, जिससे कश्मीर घूमने आए यात्री ट्रेन के बाहर के प्राकृतिक नजारों, जैसे पहाड़,



नदियाँ और टनलों का 360 डिग्री से नजारों का आनंद ले सकते हैं। यह कोच कश्मीर की जगह अन्य पर्यटन स्थल जैसे कॉकण रेलवे और दार्जिलिंग में वर्तमान में चलाए जा रहे हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिधल ने यात्रियों को दी जाने वाली विशेष, सुविधा पर बताया, " कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और विस्टाडोम कोच यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और यादगार बनाएंगे। यह यात्री सुविधाओं में एक पहल, जो कांच की छत से आसमान का नजारा और बड़ी खिड़कियों से यात्रियों को प्राकृतिक खूबसूरती का अहसास उनके सफर को रोमांचक बनाएंगी।

भारतीय रेलवे ने क्षमता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारत भर में प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) : भारतीय रेलवे ने रेल अवसंरचना परियोजनाओं के एक व्यापक सेट को मंजूरी दी है, जिनका मकसद भीड़भाड़ को कम करना, लाइनों की क्षमता बढ़ाना, सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना और देश भर में यात्रियों और माल ढुलाई को तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना है। ये स्वीकृतियाँ दक्षिण, उत्तरी और दक्षिण पूर्वी रेलवे में लागू की गई हैं, जिनमें लाइन दोहराकरण, तीसरी और चौथी लाइन, बाईपास कॉरिडोर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शामिल हैं।

झारखंड में बारबंडा-दमरुधु दोहरीकरण और दमरुधु-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइन दोहराकरण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत प्रमुख क्षमता विस्तार परियोजनाएँ हैं और भारत के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर की आधारशिला हैं। वर्तमान में, यह लाइन 108% उपयोग पर चल रही है, जिसमें ट्रेनों का ठहराव 90-150 मिनट के बीच रहता है और प्रतिदिन 78 ट्रेनों (38 यात्री और 40 मालगाड़ी) का संचालन करती है, जिससे 35.22 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की माल ढुलाई क्षमता प्राप्त होती है। हस्तक्षेप के बगैर वर्ष 2028-29 तक उपयोग 132% तक पहुंचने का अनुमान है। यह परियोजना सेंट्रल कोलफील्ड्स, सीमेंट और स्टील संयंत्रों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो और बोकारो स्टील सिटी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र सहित प्रमुख



औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों से संपर्क को मजबूत करती है। क्षमता में वृद्धि करके, यह विस्तार ऊर्जा लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता में सीधे सुधार करेगा। सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के उन मार्गों पर 34 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) को कार्यान्वयन में मंजूरी दे दी है, जहां कवच प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें 292.24 करोड़ की लागत से दिल्ली डिवीजन के 21 स्टेशन और 129.17 करोड़ की लागत से अंबाला डिवीजन के 13 स्टेशन शामिल हैं। इस आधुनिक सुविधाओं से ट्रेनों का संचालन तेज और सुरक्षित हो सकेगा, सिग्नलिंग प्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार होगा, उच्च घनत्व वाले मार्गों पर ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ेगी और आधुनिक ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों को पूरक बनाया जा सकेगा।

सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव : क्या बदला है और यह क्यों ज़रूरी है

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

महंगाई देश के सबसे अहम आर्थिक संकेतकों में से एक है, जिससे आम लोग रोजगारी की जिदगी में सीधे महसूस करते हैं, जैसे घर का राशन, किराया और पेट्रोल-डीज़ल के खर्च में बढ़तीरी से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) इसी महंगाई को मापता है। यह उन चीज़ों और सेवाओं के दाम देखता है, जिनका इस्तेमाल आम परिवार रोज़ करता है। सरल शब्दों में, सीपीआई आम आदमी की जिदगी को आइना है। यह बताता है कि थाली में खाने का खर्च कितना बढ़ा, घर का किराया कितना हुआ, और काम पर जाने के लिए ईंधन कितना महंगा हुआ।

सीपीआई भले ही एक आंकड़ा लगता हो, लेकिन यह सरकार को यह समझने में मदद करता है कि लोगों पर महंगाई का असली असर क्या है। इसी

आधार पर वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले किए जाते हैं, ताकि ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें।

भारतीय रिज़र्व बैंक भी ब्याज दर और महंगाई को नियंत्रित करने जैसे फैसलों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई को ही सबसे मुख्य पैमाना मानता है। इसलिए जब सीपीआई ज़मीन की हकीकत सही तरीके से दिखाता है, तब सरकार और आरबीआई की नीतियाँ भी लोगों की असली परेशानियों के अनुसार बेहतर बन पाती हैं।

महंगाई सिर्फ दाम बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि दामों में बदलाव से घर के बजट पर कितना असर पड़ता है। इसलिए जितना ज़रूरी

दामों को मापना है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि महंगाई का सूचकांक लोगों की आज़ की खर्च करने की आदतों को सही तरीके से दिखाए। इसी संदर्भ में भारत में सीपीआई के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 किया जा रहा है।

पिछली बार आधार बदले जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। शहरों की आबादी बढ़ी है, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण खरीदारी का तरीका बदला है और घरों का खर्च अब कई नई चीज़ों पर होने लगा है। इसीलिए नया सीपीआई 2024 तैयार करने में 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल



सौरभ गर्ग
(संशोधक, आर्थिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मेंडलावर, भारत सरकार)

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता : विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत का यूरोप के साथ 250 ईसा पूर्व से एक समृद्ध व्यापारिक संबंध रहा है, जो सिल्क रोड से भी पहले की अवधि है। अगले 2000 वर्षों के अधिकांश हिस्से के दौरान, भारतीय मसलिन, कपास, हस्तशिल्प, मसाले, पत्रा और रत्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे पसंदीदा वस्तुओं में शुमार होते थे, जिनमें से अधिकांश यूरोप तक पहुंचती थीं। इन शानदार वस्तुओं के भुगतान के तौर पर भारत को सोना और चांदी मिलते थे। अपने सुनहरे दिनों में, भारत-यूरोप व्यापार ने मात्रा और पैमाने की दृष्टि से अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की।

एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से इस संबंध को सुदृढ़ करने के प्रयास 2007 में शुरू हुए थे। गंभीर मतभेदों के कारण 2013 में बातचीत को रोकना पड़ा, क्योंकि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचार अलग थे। 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई और चुनौतियों की जटिलता के बावजूद इसे केवल दोनों राजनेताओं को मजबूत प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण अंतिम रूप दिया जा सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यापार समझौते को दोनों पक्षों ने बातचीत के माध्यम से पूरा किया है,

वह अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नियम-आधारित व्यापार संबंध की पुष्टि करता है। यह समझौता ऐतिहासिक है सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें शामिल विषय और क्षेत्र व्यापक हैं; समझौता ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। यह दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का निर्माण कर सकता है, जिसमें लगभग 2 अरब लोग और 28 देश शामिल होंगे और जो वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह समझौता मुद्दों और चिंताओं के समाधान के संदर्भ में आधुनिक और नवीन है। इस समझौते में व्यापार संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अद्यतन और मूल विषयों के साथ-साथ प्रक्रिया-संबंधी प्रावधान भी हैं। यह समझौता वस्तु और सेवा; दोनों के लिए बाजार पहुंच और नियामक बाधाओं के समाधान के लिए एक नया

मॉडल स्थापित करता है, जो पारंपरिक विषयों को नवाचार-तत्वों के साथ सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति के नियमों का अध्याय सुनिश्चित करता है कि केवल वही उत्पाद जिनका पर्याप्त प्रसंस्करण या उत्पादन साझेदार देशों में हुआ है, उन्हें मूल देश का प्रमाण दिया जाएगा; इसे विस्तृत और जटिल उत्पाद-विशिष्ट नियमों के माध्यम से हासिल किया गया है, जो मौजूदा और नयी आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप हैं। इसके अलावा, यह समझौता बौद्धिक संपदा संरक्षण को पुनर्स्थापित करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सूचना प्रवाह को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करता है। वस्तु और सेवाओं के लिए बाजार खोलना: समझौते का मुख्य ध्यान दोनों पक्षों के विशाल और व्यापक बाजारों को एक-दूसरे के लिए खोलना है। यह समझौता भारत के निर्यात व्यापार मूल्य के 99 प्रतिशत से अधिक के लिए बाजार पहुंच प्रदान करता है, जिसमें कम से कम 90 प्रतिशत भारतीय निर्यात को समझौते के लागू होने पर तुरंत निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप

से, श्रम-सघन वस्तुएँ जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, लकड़ी और लकड़ी की शिल्पकला और समुद्री उत्पादों को जल्दी लाभ मिलेगा। यह रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि-प्रसंस्करण उद्योग और खनिज जैसे उद्योगों को भी जीवंत ईंधू सामान्य बाजार में अपने निर्यात को विविधता देने में सक्षम करेगा। हालाँकि, भारत के ईंधू वाहन के लिए बाजार पहुंच की अनुमति दी है, लेकिन इसे चरणबद्ध और संतुलित तरीके से टैरिफ कोटा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है। इसी तरह, यूरोपीय संघ की शराब पर भारत की छूट परेल्तु उद्योग के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ उच्च मूल्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।

सेवाओं के व्यापार के लिए भारत-ईंधू व्यापार संबंध में महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। इस समझौते के तहत भारत ने 144 सेवा क्षेत्रों में ईंधू की प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं, जो कि अभूतपूर्व हैं। इसके अलावा, गतिशीलता पर अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवरों और संविदा सेवा प्रदाताओं का अस्थायी प्रवेश और निवास सरल और भरोसेमंद होगा, जिसका अर्थ है कि भारत के प्रतिभाशाली सेवा पेशेवर ईंधू बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।



राजेश अग्रवाल
(संशोधक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मेंडलावर, भारत सरकार)

